(ख) क्या इस लेटरल रोड का निर्माण भारत-नेपाल सीमा के साथ-साथ किया जायेगा ; और

(ग) इस सड़क का निर्माण किस तिथि तक आरम्भ होने की संभावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) से (ग). दरभंगा फारबिसगंज सड़क, विकास किये जाने पर, राज्य सड़क होगी । अतः इसके निर्माण का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का होगा । एक समय इस सड़क को सामरिक महत्व के सड़क के कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास करने के प्रश्न पर रक्षा मंत्रालय के परामर्श से जांच की गई । परन्तु इसे उस अथवा किसी अन्य केन्द्रीय कार्यक्रम में शामिल करना आवश्यक नहीं पाया गया ।

Rolling Plan Concept

436. SHRI G. S. REDDI:
SHRI MANORANJAN BHAKTA:
SHRI K. MALLANNA:
PROF. P. G. MAVALANKAR:
SHRI C. K. JAFFER SHARIEF:
SHRI PRASANNBHAI MEHTA:
DR. HENRY AUSTIN:
SHRI O. V. ALAGESAN:
SHRI SANTOSHRAO GODE:
SHRI S. D. SOMASUNDARAM:
SHRI ISHWAR CHAUDHRY:
SHRI UGRASEN:
SHRI S. S. SOMANI:

Will the Minister of PLANNING be pleased to state :

(a) whether Government have decided to introduce the rolling plan concept;

(b) if so, main features thereof; and

(c) whether the National Development Council has accepted this concept?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) and (b). The rolling plan concept is intended to make the medium-term investment plan more flexible and realistic. Initially, the projections of aggregate savings and investment, sectoral outlays and output targets for major sectors will be determined for the period 1978—83. The planning horizon will thereafter be extended by one year at a time, working out the targets and projections for one additional year at the end of each year.

The Rolling Plan system has certain advantages in that projections are made from a base level which is adjusted annually, it allows for continuous corrections of errors and provides a constant time horizon for investment decisions.

The modifications proposed in the Planning system will not mean either the abandonment of perspective planning or the replacement of the discipline of a five year framework by ad hoc annual decision making. A new 15 year perspective will be prepared for charting the longer term course of development of the economy, taking demographic factors into account. This will also provide the framework for investment decisions on long gestation projects, for which a five year time horizon is inadequate and for planning of land use, water resources, oil and mineral development and manpower.

(c) Proposed changes in the planning system including the introduction of the Rolling Plan will be submitted to the National Development Council for consideration early next year, together with the Draft Plan for 1978—83.

अल्पसंख्यकों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग

437. **श्री हरगोविन्द वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अल्पसंख्यकों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिये आयोग स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) क्या पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिये पिछड़े वर्गों के आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनिक लाल मण्डल): (क) से (ग). यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने नागरिक अधिकार आयोग का गठन करने के बारे में सिद्धांत रूप में निर्णय किया है कि अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा